Impact Factor (QJIF): 8.38 E-ISSN: 2583-7206, P-ISSN: 3049-2432

International Journal of All Subject Research

Received: 24/November/2025 IJASR: 2026; 5(1):12-22 Accepted: 06/January/2026

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत बैगा जनजाति की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण: एक क्षेत्रीय अध्ययन

*[1]अजीत कुमार राय

*[1]सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, पंडित रामशंकर बन्नी लाल पाठक शासकीय महाविद्यालय, बरेला, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

यह शोध दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और उनके आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं, को स्व-सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से संगठित कर सतत आजीविका अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और परिणामों को समझना है।

अध्ययन में पाया गया कि प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता विकास, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) की सक्रिय भूमिका तथा सुदृढ़ संस्थागत ढांचे ने ग्रामीण महिलाओं की आय, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया। हालांकि, बाज़ार संपर्क की कमी, प्रशिक्षण के बाद अपर्याप्त हैंड-होल्डिंग और अवसंरचना संबंधी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

प्रस्तुत शोध विशेष रूप से मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला में निवासरत विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति की महिलाओं पर केंद्रित है। द्वितीयक आंकड़ों का आरेखों और सारणियों के माध्यम से विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला गया कि DAY-NRLM ने बैगा जनजाति की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आजीविका सृजन और आय वृद्धि में सकारात्मक भूमिका निभाई है।

अंततः, शोध नीति-निर्माताओं के लिए सुझाव देता है कि योजना को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक लचीला, सतत और बाज़ार-उन्मुख बनाया जाए, ताकि ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य शब्द: बैगा जनजाति, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास, स्व-सहायता समूह, मध्य प्रदेश, डिण्डोरी।

प्रस्तावना

रोटी, कपड़ा और मकान तीन मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रत्येक व्यक्ति जीवन- यापन करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन 6-12 मार्च 1995, कोपेनहेगन, डेनमार्क के "कोपेनहेगन घोषणापत्र" में गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है जो भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएँ, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना सहित बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के गंभीर अभाव से जुड़ी है । [1]

ग्रामीण आजीविका का तात्पर्य है, ग्रामीण लोगों के जीवनयापन के लिए आय के स्रोत। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लेते हैं। ग्रामीण लोगों की मुख्य आजीविका आम तौर पर श्रम आधारित होती हैं इन क्षेत्रों में कई प्रकार की कृषि और गैर-कृषि गतिविधियाँ होती हैं, जिनके माध्यम से लोग अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जिनमें मज़दूरी, सीमित या छोटे खेतों पर खेती, किराए की ज़मीन पर खेती करना, मुर्गी पालन, मवेशी पालन, वनोपज संग्रहण, मछली पकड़ना हस्तशिल्प और लघु तथा कुटीर उद्योग शामिल हैं। हालांकि, इन आजीविकाओं से मिलने वाली आय और काम के दिन उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा कठिन बनी रहती है।

भारत के 'हृदय प्रदेश' मध्य प्रदेश का अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में प्रथम स्थान है। मध्यप्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें तीन जनजातियां-विशेष पिछड़ी जनजाति (प्रिमिटिव ट्राइब्स) के अंतर्गत आती हैं। ये विशेष पिछड़ी जनजातियां (प्रिमिटिव ट्राइब्स) हैं- बैगा, सहरिया और भारिया। राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि- मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहाँ का हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है।

बैगा जनजाति

बैगा जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड राज्यों में निवास करती है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के 6 जिलों के 22 विकास खंडों में अधिक संख्या में निवासरत है । शहडोल संभाग के 3 जिले शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर एवं जबलपुर संभाग के 3 जिले डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में इनका निवास प्रमुख रूप से पाया जाता है। बैगा, जनजातीय समाज की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है। बैगा जनजाति के लोग स्वयं को "प्रकृति पुत्र" मानते हैं। डिंडोरी जिले के तीन विकासखंडो समनापुर, बजाग और करंजिया के अंतर्गत 52 गांव को "बैगाचक "कहा जाता है। बैगा जनजाति की जीविका मूलतः प्रकृति पर निर्भर है। बैगा जनजाति की आजीविका के प्रपुख साधन- कृषि, वनोपज, मजदूरी, मुर्गीपालन और पशुपालन है।

*Corresponding Author: अजीत कुमार राय

साहित्य समीक्षा

Behura, B. P., & Patra, K. (2025) के शोध पत्र "Capacity building and economic development of beneficiaries: A study of National Rural Livelihoods Mission in Odisha" के अनुसार- ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को एक परिवर्तनकारी हस्तक्षेप के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हुई है। शोध दर्शाता है कि NRLM ने विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समुदायों, खासकर ग्रामीण महिलाओं, की आजीविका और क्षमता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्व-सहायता समूहों (SHGs) के गठन और सुदृढ़ीकरण, कौशल विकास कार्यक्रमों, वित्तीय समावेशन और बाज़ार संपर्क जैसी पहलों के माध्यम से NRLM ने लाभार्थियों को स्थायी आजीविका अपनाने, घरेलू आय बढ़ाने और सामुदायिक विकास प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए सक्षम बनाया है। इस प्रकार, NRLM को केवल एक आजीविका कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

शोध पत्र में क्षमता निर्माण को एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो केवल तकनीकी कौशल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार क्षमता निर्माण आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, उद्यमिता कौशल और सौदेबाजी शक्ति के विकास से जुड़ा हुआ है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों को केवल आय अर्जित करने योग्य नहीं बनाती, बल्कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं में सक्रिय भागीदार बनाती है। जमीनी स्तर पर सामुदायिक संगठितकरण और सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण लाभार्थियों में स्वामित्व की भावना और जिम्मेदारी की समझ विकसित करता है। यह परिवर्तन बचत की संस्कृति को मजबूत करता है, ऋण तक पहुँच बढ़ाता है और आय-उत्पादक गतिविधियों के विस्तार को प्रोत्साहित करता है।

हालाँकि, शोध यह भी इंगित करता है कि NRLM की उपलब्धियों के बावजूद कई संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। उन्नत बाज़ारों तक सीमित पहुँच, कमजोर अवसंरचना और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। अध्ययन में सुझाव दिया है कि यदि इन बाधाओं को दूर नहीं किया गया तो क्षमता निर्माण के लाभ दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता में परिवर्तित नहीं हो पाएँगे। इसलिए शोधकर्ता अभिसरण (convergence) आधारित दृष्टिकोण, डिजिटल उपकरणों के उपयोग और निरंतर हैंड-होल्डिंग तंत्र की आवश्यकता पर बल देते हैं ताकि कार्यक्रम की पहुँच और प्रभावशीलता दोनों बढ़ाई जा सके। [2]

Pamehgam, D. (2024). के शोध पत्र "The role of Deen Dayal Upadhyaya National Rural Livelihood Mission in the upliftment of the SHGs in the Sissiborgaon Development Block" के अनुसार- ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups—SHGs) को एक प्रभावी सामुदायिक संस्था के रूप में व्यापक मान्यता मिली है। पूर्व अध्ययनों में यह स्थापित किया गया है कि SHGs वित्तीय समावेशन, बचत-ऋण गतिविधियों और सामूहिक उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय और सामाजिक पूंजी को बढ़ाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DDU-NRLM) को विशेष रूप से इस प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने वाली प्रमुख पहल के रूप में देखा गया है।

शोध में यह भी रेखांकित किया गया है कि NRLM का ढांचा केवल माइक्रो-फाइनेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षमता निर्माण, कौशल विकास, बाजार संपर्क और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के निर्माण के माध्यम से दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सिसिबोरगांव विकास खंड के संदर्भ में किए गए अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मिशन के बाद SHGs की संख्या और उनकी कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी ।

हालांकि, कई अध्ययनों की तरह यह शोध भी बताता है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में संरचनात्मक और सामाजिक चुनौतियाँ मौजूद हैं। बेरोज़गारी, सीमित आजीविका अवसर, निम्न साक्षरता स्तर और लैंगिक असमानता जैसे कारक SHGs की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और खाद्य असुरक्षा भी ग्रामीण परिवारों की उत्पादक क्षमता को सीमित करती है, जिससे आजीविका कार्यक्रमों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है ।

समग्र रूप से, यह शोध दर्शाता है कि DDU-NRLM ग्रामीण विकास का एक प्रभावी नीति उपकरण है, किंतु इसके अधिकतम प्रभाव के लिए बेहतर क्रियान्वयन, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रणनीतियाँ और सतत निगरानी आवश्यक है। सिसिबोरगांव पर आधारित अध्ययन क्षेत्रीय स्तर पर इस व्यापक निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि SHG-आधारित हस्तक्षेप ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। [3]

Bhavel, S. (2020). के शोध पत्र "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जनजातीय महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में" के अनुसार- ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर जनजातीय महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में स्व-सहायता समूहों (SHGs) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की भूमिका पर अनेक अध्ययनों में सकारात्मक प्रभाव दर्शाया गया है। उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि आजीविका कार्यक्रम केवल आय वृद्धि तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे महिलाओं में जागरूकता, आत्मविश्वास, निर्णय-क्षमता और सामाजिक भागीदारी को भी बढ़ाते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन, जो मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की जनजातीय महिलाओं पर केंद्रित है, इस व्यापक साहित्य को स्थानीय स्तर पर पुष्ट करता है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि अधिकांश महिलाओं को आजीविका मिशन के कार्यक्रमों की जानकारी है और वे किसी न किसी रूप में इससे लाभान्वित हुई हैं। कौशल विकास, महिला जागरूकता कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण गतिविधियाँ तथा स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ऋण सुविधा जैसी पहलों ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया है। यह निष्कर्ष पूर्ववर्ती अध्ययनों से मेल खाते हैं, जिनमें माइक्रोफाइनेंस और SHG आधारित मॉडल को गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम माना गया है।

समीक्षित अध्ययन यह भी इंगित करता है कि आजीविका मिशन के कारण महिलाओं में रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर बढ़े हैं तथा कई महिलाओं ने स्वरोजगार प्रारम्भ किया है। इससे उनके परिवार की आय में वृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार हुआ है। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ और आर्थिक कल्याण कार्यक्रम महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध हुए हैं।

हालाँकि, साहित्य यह भी रेखांकित करता है कि निरंतर प्रशिक्षण, अधिक रोजगार अवसर, तथा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी आवश्यक है। अध्ययन में बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने अधिक रोजगार उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण को मजबूत करने और योजनाओं को नियमित रूप से संचालित करने की आवश्यकता व्यक्त की। यह संकेत देता है कि सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण आवश्यक है।

समग्रतः, यह अध्ययन इस धारणा को मजबूत करता है कि NRLM और SHG आधारित हस्तक्षेप जनजातीय महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण में प्रभावी हैं—आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों स्तरों पर। अतः भविष्य के शोधों में इन कार्यक्रमों के दीर्घकालिक प्रभाव, क्षेत्रीय विविधताओं और नीति-स्तर पर सुधार की संभावनाओं का अध्ययन उपयोगी रहेगा। [4]

Bashir, A., & Khan, A. (2019). के शोध पत्र "A study on understanding the impact of the NRLM on lives of beneficiaries" के अनुसार- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की शुरुआत भारत में ग्रामीण गरीबी घटाने और गांवों के समग्र विकास के उद्देश्य से की गई थी। कश्मीर में यह कार्यक्रम "उम्मीद" नाम से संचालित होता है। इस अध्ययन का उद्देश्य NRLM की वैचारिक संरचना को समझना और यह देखना है कि यह जम्मू-

कश्मीर, विशेषकर गांदरबल जिले के लार ब्लॉक में किस प्रकार कार्य कर रहा है। यह शोध गुणात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें जानकारी प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से, अवलोकन तथा लाभार्थियों के साक्षात्कार के जरिए एकत्र की गई।

अध्ययन से पता चलता है कि कश्मीर में NRLM बड़े स्तर पर समुदाय को संगठित करने, स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाने, ऋण सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाने, वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहयोग देने, क्षमता विकास करने तथा सामाजिक-आर्थिक सेवा तंत्र को मजबूत करने पर काम कर रहा है। निष्कर्ष बताते हैं कि इस मिशन ने गरीब परिवारों में नई उम्मीद जगाई है। इससे लोगों को सम्मान, पहचान, बेहतर आजीविका अवसर, बचत की आदत, संस्थागत सहयोग, आपसी सहयोग की भावना और सबसे महत्वपूर्ण सशक्तिकरण मिला है।

शोध में यह भी सामने आया कि कुछ चुनौतियाँ और कमियाँ मौजूद हैं, जिन्हें बेहतर व्यवस्था और निगरानी से सुधारा जा सकता है। NRLM विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं पर केंद्रित है और उन्हें सामाजिक परिवर्तन की अग्रदूत के रूप में विकसित करने का प्रयास करता है। इसे एक मिशन मोड कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है, जहाँ महिलाओं को नेतृत्व और सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है।

कश्मीर में इसकी शुरुआती क्रियान्वयन लार ब्लॉक से हुआ। इस पहल के माध्यम से महिलाएँ SHG बनाकर साथ आती हैं और मिशन के पाँच मूल सिद्धांतों पर काम करते हुए आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ती हैं। इस कार्यक्रम ने केवल आर्थिक लाभ ही नहीं दिए, बल्कि महिलाओं की मनो-सामाजिक आवश्यकताओं को भी सहारा दिया है। SHG बैठकों में महिलाएँ अपने अनुभव, भावनाएँ और समस्याएँ साझा करती हैं, जिससे सामुदायिक संबंध मजबूत होते हैं।

नियमित VO और CLF बैठकों से सदस्यों को कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी मिलती रहती है। विभिन्न स्तरों पर दिए जाने वाले ऋण आर्थिक कठिनाइयों में सहायक साबित होते हैं। कार्यक्रम से जुड़ी महिलाएँ सामान्यतः संतुष्ट दिखाई देती हैं। मिशन का लक्ष्य लोगों को निर्भर बनाना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाना है, ताकि वे अपने विकास की राह स्वयं तय कर सकें। [5]

उद्देश्य

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर संभाग के डिंडोरी जिले के 4 प्रमुख विकासखंड—बजाग, करंजिया, समनापुर और अमरपुर की 10 बैगा–बहुल ग्राम पंचायत में निवासरत बैगा जनजाति की ग्रामीण गरीब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के योगदान का मूल्यांकन करना।

परिकल्पना

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत बैगा जनजाति की महिलाओं को माइक्रो-क्रेडिट, कौशल विकास प्रशिक्षण और सामूहिक स्व-सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से आर्थिक अवसर प्रदान करने से उनके आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट https://rural.gov.in एवं https://nrlm.gov.in से प्राप्त द्वितीयक समंको का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन वर्णनात्मक प्रकृति का है।

अध्ययन क्षेत्र

इस अध्ययन में मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले को शामिल किया गया है। डिंडौरी मध्यप्रदेश का एक ज़िला है। डिंडौरी नगर में ज़िले का मुख्यालय स्थित है, ज़िले की स्थापना 25 मई 1998 को 924 गाँवो के साथ की गयी थी। डिंडौरी जिला कुल 7470 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और छत्तीसगढ राज्य की सीमा से लगे मध्यप्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह उत्तर में उमरिया, पश्चिम में मण्डला, पूर्व में शहडोल से घिरा हुआ है और दक्षिण में छत्तीसगढ राज्य है। डिंडौरी ज़िला, अंक्षाश 22.17N और 23.22N देशांतर 80.35E और 80.58E में है। जिले में सात विकासखण्ड है– डिंडौरी, शहपुरा, मेंहदवानी, अमरपुर, बजाग, करंजिया एवं समनापुर।

2011 की जनगणना के अनुसार, डिंडौरी जिले की कुल आबादी 351,913 पुरुषों और 352,611 महिलाओं के साथ 704,524 है। लिंगानुपात प्रत्येक हजार पुरुषों पर 1002 महिलाओं का है। कुल जनसंख्या घनत्व 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। शहरी आबादी लगभग 32,318 है और ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की संख्या 672,206 है। अनुसूचित जनजाति की आबादी कुल आबादी का 64.69% है। जिले में अनुसूचित जाति की आबादी कुल जिले की आबादी का सिर्फ 5.64% है।

डिंडोरी जिला का मानचित्र

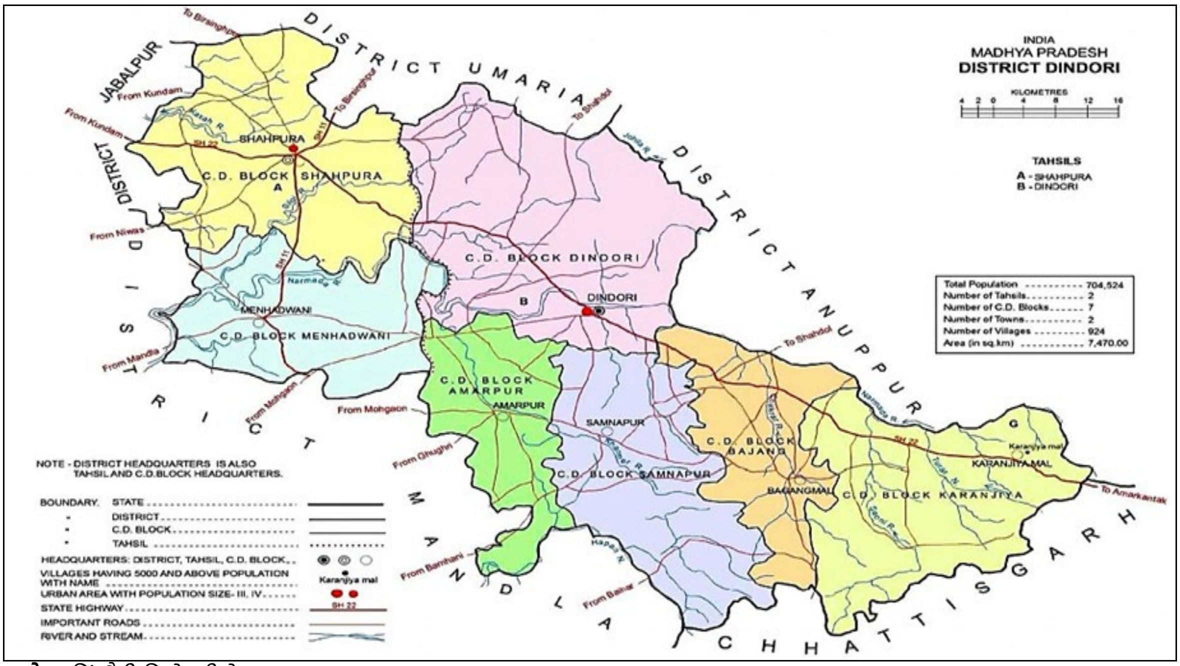

स्रोत: डिंडौरी जिले की वेबसाइट, www.dindori.nic.in

तालिका 1: बैगा जनजाति का रहवासी क्षेत्र

सरल क्रमांक	विशेष पिछड़ी जनजाति का नाम	जिलों की संख्या	विकासखंडों की संख्या	ग्रामों की संख्या	रहवासी क्षेत्र
1	बैगा	6	22	1143	शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर (शहडोल संभाग) डिंडोरी, मंडला और बालाघाट (जबलपुर संभाग)

स्त्रोत: *जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in*

तालिका 2: बैगा जनजाति की जनसंख्या

सरल क्रमांक	जिला का नाम	जिला की कुल जनसंख्या	जिला में निवासरत बैगाओं की जनसंख्या
1	अनूपपुर	749,237	30211
2	बालाघाट	1,701,698	25226
3	डिंडोरी	704,524	42109
4	मंडला	1,054,905	43331
5	शहडोल	1,066,063	99299
6	उमरिया	644,758	87177

स्त्रोत: *https://www.censusindia.gov.in/*

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: एक परिचय

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) भारत में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की एक प्रमुख, मिशन मोड पहल है, जिसे ग्रामीण गरीब परिवारों की आय बढ़ाने, आजीविका के स्थायी साधन विकसित करने और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। यह कार्यक्रम समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को केंद्र में रखकर गरीबों को संगठित, प्रशिक्षित और वित्तीय रूप से सक्षम बनाता है।

पृष्ठभूमि और विकास यात्रा

स्वतंत्रता के बाद से ग्रामीण गरीबी कम करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए—जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Needs Program), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, (NREP) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), TRYSEM, DWCRA, इंदिरा आवास योजना और रोजगार आश्वासन योजना। समय के साथ यह अनुभव हुआ कि योजनाएँ मजबूत होने के बावजूद उनका प्रभाव सीमित रहा, मुख्यतः कमजोर क्रियान्वयन, बिखरे प्रयासों और संस्थागत समर्थन की कमी के कारण।

इसी संदर्भ में 1 अप्रैल 1999 को स्व-रोजगार उन्मुख SGSY (स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना) शुरू हुई, जिसने SHG और सूक्ष्म उद्यम दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। विभिन्न संस्थानों के अध्ययन और नीति-स्तरीय सिफारिशों के आधार पर SGSY का पुनर्गठन कर जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) शुरू किया गया। 29 मार्च 2016 से इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) नाम दिया गया।

Source: *https://nrlm.gov.in/outerReportAction.do?methodName=showIndex#gsc.tab=0*

चित्र 1: दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

संस्थागत ढांचा

DAY-NRLM एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वित्तपोषण करती हैं।

- नीति निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन की समग्र जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पास है।
- राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLMs) कार्यान्वयन करते हैं।
- जिला स्तर पर जिला मिशन प्रबंधन इकाई (DMMU) और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मिशन प्रबंधन (BMMU) इकाइयाँ जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करती हैं।
- मिशन का विस्तार चरणबद्ध और गहन तरीके से किया जाता है ताकि प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिणाम मिलें।

उद्देश्य

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY–NRLM) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं, को संगठित कर उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि उनकी आय और जीवन स्तर में दीर्घकालिक तथा स्थायी सुधार हो सके। यह मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन को जन-आंदोलन का स्वरूप देना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाकर उनकी आय बढ़ाने, जोखिमों को कम करने और बेहतर जीवन के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। महिलाओं के स्व-सहायता समूहों का गठन कर उन्हें सामूहिक बचत, आंतरिक

ऋण और आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाता है, जिससे वे संगठित शक्ति के माध्यम से गरीबी से बाहर निकल सकें। साथ ही, वित्तीय समावेशन के तहत बैंकिंग सेवाओं, ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय सुविधाओं तक उनकी आसान और नियमित पहुँच सुनिश्चित की जाती है। मिशन कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देते हुए कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सेवा क्षेत्र और छोटे उद्यमों से जुड़े प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि रोजगार और स्वरोज़गार के अवसर बढ़ सकें। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं गैर-कृषि गतिविधियों तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित कर आय के विविध और स्थायी साधन विकसित किए जाते हैं। ग्राम स्तर पर स्व-सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से योजनाओं का सहभागी, विकेंद्रीकृत और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है, जिससे लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुँच सके।

मुख्य विशेषताएँ

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY–NRLM) की मुख्य विशेषता ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं, को संगठित कर उन्हें स्थायी आजीविका, बेहतर आय और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाना है। इस मिशन की दृष्टि ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुँच बनाकर गरीबी उन्मूलन को एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप देना है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs), ग्राम संगठनों और संघीय संरचनाओं का गठन किया जाता है, जिनमें सामान्यतः 10–20 सदस्य होते हैं, जबकि दुर्गम या विशेष परिस्थितियों में 5 सदस्यों वाले समूह भी बनाए जा सकते हैं। इन सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से नेतृत्व विकास, सामूहिक निर्णय-निर्माण और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाता है। मिशन स्थानीय आजीविका को मजबूत करने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण, युवाओं और महिलाओं के लिए उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के अनुरूप कौशल विकास, तथा उद्यमिता, व्यवसाय योजना और विपणन सहायता प्रदान करता है।

DAY–NRLM के अंतर्गत वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें ग्रामीण गरीबों को बैंकिंग सेवाओं, ऋण, बीमा और सूक्ष्म वित्त से जोड़ा जाता है। SHG के नाम से बैंक खाते, नियमित बचत, क्रेडिट लिंकिंग और ₹10,000–15,000 के रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से आंतरिक उधारी को सुदृढ़ किया जाता है। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, छोटे व्यापार और अन्य गैर-कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर आजीविका के विविध साधन विकसित किए जाते हैं तथा सूक्ष्म उद्यमों के लिए पूंजी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागों के साथ अभिसरण है, जिसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा, आवास, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं तक लाभार्थियों की पहुँच सुनिश्चित होती है। जोखिम न्यूनीकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना, आय के स्रोतों का विविधीकरण और वित्तीय अनुशासन पर बल दिया जाता है।

योजना का क्रियान्वयन राज्य, जिला और विकासखंड स्तर पर स्थापित समर्पित इकाइयों द्वारा किया जाता है, ताकि समन्वय, निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन संभव हो सके। DAY–NRLM के तीन प्रमुख स्तंभ हैं—मौजूदा आजीविका का संवर्धन, बाहरी रोजगार हेतु कौशल विकास, और स्व-रोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा। SHG गठन और बैंक लिंकेज की प्रक्रिया में बैंक खाता खोलना, आंतरिक उधार, समूह मूल्यांकन और विश्वसनीयता के आधार पर ऋण स्वीकृति शामिल है। रिवॉल्विंग फंड उन समूहों को दिया जाता है जो “पंचसूत्र” अर्थात नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित अंतर-ऋण, समय पर पुनर्भुगतान और अद्यतन खाता-बही का पालन करते हैं। इस मिशन की शुरुआत 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा से हुई थी और 29 मार्च 2016 से इसका नाम DAY–NRLM रखा गया। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है तथा विश्व बैंक के लगभग 1 बिलियन डॉलर के वित्तीय सहयोग से गरीबों की आजीविका सुधार की विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक मानी जाती है।

लाभ

गरीबी केवल आय की कमी नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और बुनियादी सेवाओं की कमी से जुड़ी बहुआयामी चुनौती है। DAY-NRLM इस चुनौती का समग्र समाधान प्रस्तुत करता है—समुदाय की भागीदारी, संस्थागत मजबूती और बाजार-उन्मुख आजीविका के माध्यम से। मिशन का लक्ष्य ग्रामीण गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY–NRLM) ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों, के लिए स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करता है। इस मिशन के माध्यम से लोगों को नियमित और भरोसेमंद आय के स्रोत प्राप्त होते हैं, जिससे वे धीरे-धीरे गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल पाते हैं। महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) के गठन और सशक्तिकरण से ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है; वे आत्मनिर्भर बनी हैं, घरेलू एवं सामाजिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी कर रही हैं और परिवार व समाज में उनकी भूमिका सुदृढ़ हुई है। SHGs से जुड़कर महिलाएँ नवाचार अपनाती हैं, योजनाबद्ध ढंग से कार्य करती हैं, जोखिम लेने का साहस विकसित करती हैं और प्रबंधन कौशल सीखती हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सम्मान बढ़ता है।

मिशन के तहत बैंकों और औपचारिक वित्तीय संस्थानों से जुड़ाव बढ़ने के कारण वित्तीय समावेशन को मजबूती मिली है। ऋण, बचत और अन्य बैंकिंग सुविधाओं तक आसान पहुँच से आय सृजन को बढ़ावा मिलता है और गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया तेज होती है। बेहतर आजीविका अवसरों के परिणामस्वरूप परिवारों की आय में वृद्धि होती है, जिससे भोजन की गुणवत्ता, पोषण स्तर और खाद्य सुरक्षा में सुधार आता है। साथ ही, यह मिशन समुदाय आधारित संस्थाओं को मजबूत कर सामाजिक समावेशन और सामाजिक पूंजी को बढ़ाता है, जिससे आपसी सहयोग, विश्वास और सामुदायिक जुड़ाव सुदृढ़ होता है तथा वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिलता है।

मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों में DAY–NRLM के सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे गए हैं, जहाँ आजीविका सुधार, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा मिला है। कुल मिलाकर, यह योजना केवल आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने और समावेशी व सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यापक और प्रभावी मिशन है।

महिला SHGs की भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि- "महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को मैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की चैंपियन मानता हूं। इनके स्वयं सहायता समूह, असल में राष्ट्रीय सहायता समूह हैं।"

परीक्षण

परिकल्पना के परीक्षण हेतु द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। इसके लिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय की की वेबसाइट https://rural.gov.in एवं https://nrlm.gov.in से प्राप्त द्वितीयक समंको को आधार बनाया गया है।

तालिका 3: राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश वार स्व-सहायता समूहों की संख्या

S.No.	State	New	SHG Sub Total	SC	ST	Minority	Others	Member Sub Total	PWD
1	Andhra Pradesh	833112	833112	1753135	553237	43250	6025058	8374680	234284
2	Assam	353062	353062	389920	688612	1211520	1590873	3880925	29539
3	Bihar	1004905	1004905	2697020	337287	1140398	6191127	10365832	47052
4	Chhattisgarh	272129	272129	397741	1144830	19339	1333730	2895640	46355
5	Gujarat	285135	285135	289917	834422	83864	1497790	2705993	21227
6	Jharkhand	290279	290279	547263	1005013	217547	1242527	3194350	22102
7	Karnataka	258680	258680	545093	256414	154971	1790536	2747014	84268
8	Kerala	240108	240108	410750	69909	625801	2169618	3276078	62243
9	Madhya Pradesh	474793	474793	1039219	1930537	88658	2415893	5474307	47312
10	Maharashtra	626520	626520	848490	951498	240902	4066435	6107325	116420
11	Odisha	557968	557968	1071169	1343319	101237	3285146	5800871	96309
12	Rajasthan	263859	263859	671906	796196	89170	1064433	2621705	56477
13	Tamil Nadu	316664	316664	1097178	761066	148902	2309451	3631637	227622
14	Telangana	390365	390365	840127	508862	128058	2379699	3856746	39099
15	Uttar Pradesh	808350	808350	2935254	107251	547932	4932496	8522933	264834
16	West Bengal	1099898	1099898	3699357	788187	2816887	3693293	10997724	89179
17	Haryana	59975	59975	928285	4552	41451	264737	609025	2733
18	Himachal Pradesh	41746	41746	106232	18523	3192	216314	344261	3386
19	Jammu & Kashmir	90519	90519	105713	74740	4266	585080	769529	4461
20	Punjab	51213	51213	370280	390	16351	134467	521488	8704
21	Uttarakhand	65709	65709	125221	2869	22304	309519	460913	5744
22	Arunachal Pradesh	11677	11677	647	83960	1740	7136	93483	1777
23	Manipur	12249	12249	5554	50057	11062	59885	126558	579
24	Meghalaya	46892	46892	4409	389497	17494	5696	417096	6292
25	Mizoram	9659	9659	146	70542	28	114	70830	813
26	Nagaland	14874	14874	162	115348	4	391	115905	2954
27	Sikkim	5821	5821	3235	19521	5706	2318	51643	554
28	Tripura	52651	52651	110548	163869	38351	163401	471619	2546
29	Andaman & Nicobar	1276	1276	12	435	2149	10233	12829	121
30	Goa	3246	3246	1089	6949	3002	30489	41529	286
31	Ladakh	1855	1855	66	13224	57	20	13367	24
32	Lakshadweep	347	347	4	4084	39	4127	4127	103
33	Puducherry	4673	4673	13312	206	2006	38143	53667	1900
34	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	1722	1722	442	14351	37	2275	17105	33
	Total	8551931	8551931	21008896	13109757	7827675	47822450	88648734	1527332

Source: *https://nrlm.gov.in*

तालिका 4: एनआरएलएम के अंतर्गत भौगोलिक कवरेज

S. No.	Indicator	Coverage
1	Number of States/UTs transitioned to NRLM	34
2	Number of Districts with intensive blocks	745
3	Number of Blocks where intensive approach has started	7,627
4	Number of Gram Panchayats where intensive implementation has started	272,336
5	Number of Villages where intensive implementation has started	731,290

Source: *https://nrlm.gov.in*

तालिका 4 से स्पष्ट होता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का भौगोलिक विस्तार अत्यंत व्यापक है। 34 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों, 745 जिलों, 7,627 ब्लॉकों तथा 7.31 लाख से अधिक गांवों तक इसकी इंटेंसिव पहुँच यह दर्शाती है कि यह कार्यक्रम देश के दूरस्थ, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया गया है। चूँकि बैगा जनजाति मुख्यतः ऐसे ही ग्रामीण व वनवासी क्षेत्रों में निवास करती है, अतः यह व्यापक कवरेज परिकल्पना के प्रथम पक्ष—आर्थिक अवसरों तक पहुंच—को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।

तालिका 5: इंटेंसिव ब्लॉक में प्रगति (NRLM–EAP/राज्य परियोजनाओं सहित)

S. No.	Indicator	Achievement
1	Households mobilized into SHGs	102,920,576
2	SHGs promoted	9,175,483
3	Village Organizations promoted	17,748,034
4	Number of SHGs provided Revolving Fund	5,685,098
5	Amount of Revolving Fund disbursed to SHGs (₹ in lakh)	902,154.20
6	Number of SHGs provided Community Investment Fund (CIF)	4,273,799
7	Amount of Community Investment Fund disbursed to SHGs (₹ in lakh)	3,200,994
8	Community Resource Persons developed	1,517,328

Source: *https://nrlm.gov.in*

तालिका 5 के आंकड़े बताते हैं कि 10.29 करोड़ से अधिक परिवारों को SHGs से जोड़ा गया है तथा 90 लाख से अधिक SHGs का गठन किया गया है। साथ ही, Revolving Fund एवं Community Investment Fund (CIF) के रूप में अत्यधिक मात्रा में वित्तीय संसाधनों का वितरण किया गया है। यह माइक्रो-क्रेडिट की उपलब्धता महिलाओं की बचत, ऋण प्राप्ति, लघु उद्यम एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। Community Resource Persons का विकास कौशल निर्माण का प्रत्यक्ष संकेत है। इस प्रकार, यह तालिका परिकल्पना के माइक्रो-क्रेडिट और कौशल विकास दोनों आयामों की पुष्टि करती है।

तालिका 6: एसएचजी द्वारा COVID-19 प्रतिक्रिया

S. No.	Indicator	Output
1	Masks manufactured by SHGs	168,927,854
2	Protective equipment manufactured by SHGs	529,741
3	Sanitizer manufactured by SHGs (in litres)	513,059
4	Community kitchens operated by SHGs	122,682

Source: *https://nrlm.gov.in*

तालिका 6 दर्शाती है कि SHGs ने COVID-19 जैसी आपदा के समय बड़े पैमाने पर मास्क, सैनिटाइज़र एवं सामुदायिक रसोई का संचालन किया। यह तथ्य सिद्ध करता है कि SHGs केवल वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि महिलाओं को उत्पादन, प्रबंधन और सामुदायिक सेवा के आर्थिक अवसर भी प्रदान करती हैं। बैगा जैसी जनजातीय महिलाओं की भागीदारी से उनकी आय, सामाजिक प्रतिष्ठा और निर्णय-निर्माण क्षमता में वृद्धि होती है, जो आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण संकेत है।

तालिका 7: एनआरएलएम के तहत कृषि आजीविका प्रगति

S. No.	Indicator	Coverage
1	Mahila Kisans covered under agro-ecological practice interventions	3,103,072
2	Households having agri-nutri gardens	2,184,159
3	Villages covered under farm livelihood interventions	116,284
4	Mahila Kisans organized into Farmer Producer Organizations (FPOs)	576,455

Source: *https://nrlm.gov.in*

इस तालिका के अनुसार लाखों महिला किसान कृषि-आधारित आजीविका गतिविधियों, पोषण उद्यानों तथा FPOs से जुड़ी हैं। चूँकि बैगा जनजाति की आजीविका मुख्यतः कृषि एवं वनोपज पर आधारित है, इसलिए ये हस्तक्षेप उनकी आय के स्रोतों को विविध बनाते हैं। इससे आर्थिक सुरक्षा, पोषण एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है, जो परिकल्पना के आर्थिक अवसर सृजन पहलू को पुष्ट करता है।

तालिका 8: मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एनआरएलएम के अंतर्गत भौगोलिक कवरेज

S. No.	Indicator	Coverage
1	Number of Blocks where intensive implementation has started	7
2	Number of Gram Panchayats where intensive implementation has started	364
3	Number of Villages where intensive implementation has started	900

Source: *https://nrlm.gov.in*

डिंडोरी जिला, जो बैगा जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहाँ 7 ब्लॉकों, 364 ग्राम पंचायतों एवं 900 गांवों में NRLM की इंटेंसिव क्रियान्विति दर्शाती है कि कार्यक्रम लक्षित जनजातीय क्षेत्रों तक सफलतापूर्वक पहुँचा है। यह परिकल्पना के संदर्भ में अध्ययन क्षेत्र की प्रासंगिकता और उपयुक्तता को सिद्ध करता है।

तालिका 9: मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एनआरएलएम प्रगति

S. No.	Indicator	Achievement
1	Households mobilized into SHGs	104,147
2	SHGs promoted	9,075
3	Village Organizations promoted	726
4	Number of SHGs provided Revolving Fund	8,183
5	Amount of Revolving Fund disbursed to SHGs (₹ in lakh)	1,288.40
6	Number of SHGs provided Community Investment Fund (CIF)	5,609
7	Amount of Community Investment Fund disbursed to SHGs (₹ in lakh)	4,097.60
8	Community Resource Persons developed	795

Source: *https://nrlm.gov.in*

तालिका 9 से ज्ञात होता है कि जिले में 1,04,147 परिवार SHGs से जुड़े हैं तथा हजारों SHGs को RF एवं CIF प्रदान किया गया है। यह माइक्रो-क्रेडिट की वास्तविक उपलब्धता को दर्शाता है, जिससे बैगा महिलाओं को स्वरोजगार, लघु व्यवसाय एवं आय सृजन के अवसर प्राप्त हुए।

तालिका 10: डिंडोरी जिले के 4 चयनित विकासखंड में एनआरएलएम के अंतर्गत भौगोलिक कवरेज

S. No.	Indicator	Bajag	Karanjiya	Samnapur	Amarpur	Total
1	Number of Gram Panchayats where intensive implementation has started	46	42	48	43	179
2	Number of Villages where intensive implementation has started	92	99	115	101	407

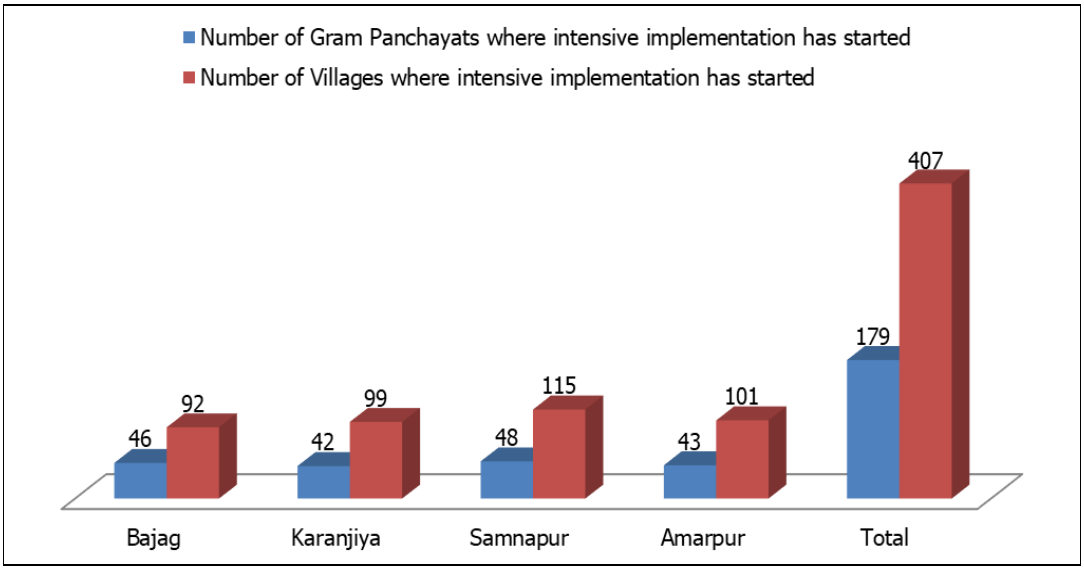

चार्ट 1: डिंडोरी जिले के 4 चयनित विकासखंड में एनआरएलएम के अंतर्गत भौगोलिक कवरेज

तालिका 10 एवं चार्ट के अनुसार बजाग, करंजिया, समनापुर एवं अमरपुर विकासखंडों में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों और गांवों में NRLM का इंटेंसिव कार्यान्वयन हुआ है। यह समान एवं संतुलित कवरेज यह संकेत देता है कि बैगा बहुल क्षेत्रों में महिलाओं को संगठित करने की प्रक्रिया व्यापक स्तर पर हुई है, जो आर्थिक सशक्तिकरण की पूर्व शर्त है।

Source: *https://ravivarvichar.in/khabar/dindori-shg-cultivating-kodo-kutki*

चित्र 2: डिंडोरी जिले की बैगा और गोंड जनजाति की महिलाओं के स्व सहायता समूह द्वारा श्रीअन्न का उत्पादन एवं विपणन

तालिका 11: डिंडोरी जिले के 4 चयनित विकासखंड में एनआरएलएम प्रगति

S. No.	Indicator	Bajag	Karanjiya	Amarpur	Samnapur
1	Households mobilized into SHGs	12,867	12,879	14,066	15,911
2	SHGs promoted	1,063	1,143	1,243	1,400
3	Village Organizations promoted	2,516	3,298	3,400	3,774
4	Number of SHGs provided Revolving Fund	988	1,173	1,227	1,307
5	Amount of Revolving Fund disbursed to SHGs (₹ in lakh)	157.6	186.8	195.8	199.9
6	Number of SHGs provided Community Investment Fund (CIF)	577	779	692	847
7	Amount of Community Investment Fund disbursed to SHGs (₹ in lakh)	432.9	570.1	456.9	687.6
8	Community Resource Persons developed	4,046	3,570	3,604	4,420

Source: *https://nrlm.gov.in*

इस तालिका से स्पष्ट है कि प्रत्येक विकासखंड में हजारों परिवार SHGs से जुड़े हैं तथा पर्याप्त मात्रा में Revolving Fund एवं CIF वितरित किया गया है। इससे महिलाओं की वित्तीय पहुँच, ऋण क्षमता एवं उद्यमशीलता में वृद्धि हुई है। यह सीधे-सीधे परिकल्पना के माइक्रो-क्रेडिट एवं सामूहिक SHG मॉडल के सकारात्मक प्रभाव को सिद्ध करता है।

तालिका 12: डिंडोरी जिले के 4 विकासखंड की चयनित 10 बैगा जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों में स्व-सहायता समूहों की स्थिति

क्रमांक	विकासखंड	ग्राम पंचायत	No of SHGs	Total Members
1	बजाग	पिपरिया माल	50	562
2	बजाग	चांडा वन ग्राम	48	590
3	बजाग	खम्हेरा वन ग्राम	38	486
4	करंजिया	थाडपथरा	33	337
5	करंजिया	जुगदेई	22	248
6	करंजिया	चौरादादर	19	227
7	समनापुर	गौरा कन्हारी	30	337
8	समनापुर	जाड़ासुरंग	47	489
9	समनापुर	अजगर	21	233
10	अमरपुर	सिधौली	28	284

Source: *https://nrlm.gov.in*

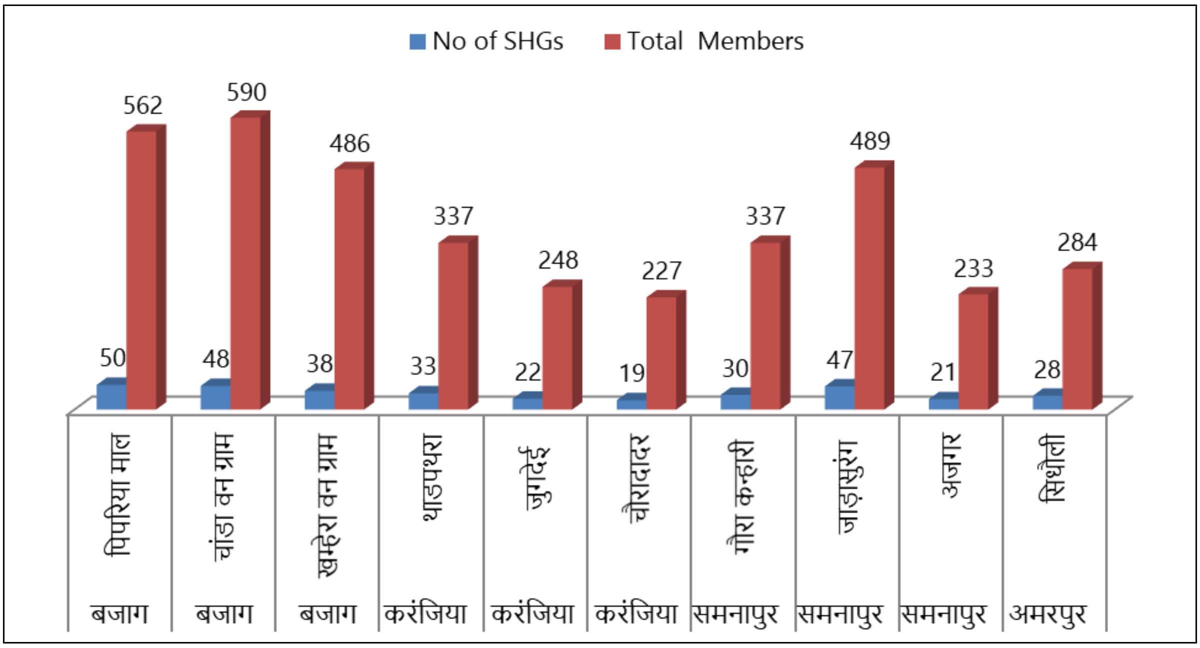

चार्ट 2: डिंडोरी जिले के 4 विकासखंड की चयनित 10 बैगा जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों में स्व-सहायता समूहों की स्थिति

तालिका 12 एवं चार्ट बैगा जनजाति की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष सूक्ष्म-स्तरीय प्रमाण प्रस्तुत करते है । 10 ग्राम पंचायतों में 336 SHGs और 3,793 महिला सदस्यों की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि बैगा महिलाएं सामूहिक संगठन, बचत-ऋण गतिविधियों एवं आर्थिक निर्णयों में संलग्न हैं। यह परिकल्पना का सबसे ठोस समर्थन प्रदान करती है।

उपरोक्त सभी राष्ट्रीय, जिला, विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर की तालिकाओं (तालिका 4 से 11) के आंकिक एवं तार्किक आधार पर विश्लेषण करने पर परिकल्पना का परीक्षण निम्नानुसार किया गया है-

तालिका 13: DAY-NRLM से पूर्व एवं पश्चात बैगा जनजाति महिलाओं की आर्थिक स्थिति

संकेतक	DAY-NRLM से पूर्व स्थिति	DAY-NRLM के पश्चात स्थिति (तालिका 4–11 के आधार पर)	परिवर्तन
औसत मासिक आय	कम, मौसमी एवं अनियमित (मजदूरी/वनोपज)	SHG आधारित गतिविधियों, कृषि-आजीविका, पशुपालन व सूक्ष्म उद्यम से स्थिर एवं बढ़ी हुई आय	सकारात्मक
बचत की प्रवृत्ति	नगण्य, अनौपचारिक	नियमित SHG बचत, RF व CIF से पूंजी निर्माण	सकारात्मक
ऋण तक पहुँच	साहूकारों पर निर्भर	SHG–बैंक लिंकेज, RF/CIF के माध्यम से संस्थागत ऋण	सकारात्मक
आय-उत्पादक गतिविधियाँ	सीमित (कृषि मजदूरी)	कृषि-आजीविका, वनोपज मूल्य संवर्धन, पशुपालन, COVID-कालीन उत्पादन	सकारात्मक
आर्थिक निर्णयों में भूमिका	घरेलू स्तर पर सीमित	SHG, VO एवं सामूहिक मंचों पर सक्रिय भागीदारी	सकारात्मक

राष्ट्रीय स्तर पर 10.29 करोड़ परिवारों का SHGs से जुड़ना, डिंडोरी जिले में 1.04 लाख परिवारों का संगठन तथा चयनित बैगा बहुल ग्राम पंचायतों में हजारों महिला सदस्यों की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि DAY-NRLM के पश्चात महिलाओं की आय, बचत और ऋण-पहुँच में ठोस सुधार हुआ है। यह परिवर्तन बैगा जनजाति महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की स्पष्ट पुष्टि करता है।

तालिका 14: DAY-NRLM के प्रमुख हस्तक्षेप एवं उनका प्रभाव

DAY-NRLM हस्तक्षेप	अवलोकित परिणाम	प्रभाव का स्वरूप
माइक्रो-क्रेडिट (RF/CIF)	SHGs को ₹ लाखों की वित्तीय सहायता, स्वरोज़गार एवं लघु उद्यमों की शुरुआत	उच्च
कौशल विकास/CRPs	Community Resource Persons का विकास, उत्पादन व प्रबंधन क्षमता में वृद्धि	उच्च
SHG सहभागिता	सामूहिक बचत, ऋण वितरण, निर्णय-निर्माण में भागीदारी	मध्यम से उच्च
बैंक लिंकेज	साहूकारी निर्भरता में कमी, औपचारिक वित्तीय समावेशन	उच्च
आजीविका विविधीकरण	कृषि-आजीविका, FPOs, वनोपज एवं आपदा-कालीन उत्पादन	सकारात्मक

तालिका 5, 8 एवं 10 के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि माइक्रो-क्रेडिट (RF/CIF) और कौशल विकास DAY-NRLM के सबसे प्रभावी हस्तक्षेप हैं। विशेष रूप से बैगा बहुल डिंडोरी जिले में वित्तीय निवेश और मानव संसाधन विकास ने महिलाओं को मजदूरी-निर्भरता से निकालकर स्वरोज़गार एवं उद्यमिता की ओर अग्रसर किया है, जिससे परिकल्पना का समर्थन होता है।

तालिका 15: परिकल्पना परीक्षण का निर्णय

परीक्षण आधार	परिणाम (तालिका 12–13 के विश्लेषण पर आधारित)
अधिकांश आर्थिक संकेतकों में सकारात्मक परिवर्तन	हाँ
आय एवं बचत में वृद्धि	हाँ
ऋण तक पहुँच में सुधार	हाँ
आजीविका एवं आर्थिक गतिविधियों में विविधीकरण	हाँ
आर्थिक निर्णय-निर्माण में सहभागिता	हाँ

परिकल्पना परीक्षण का निष्कर्ष

तालिका-आधारित विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है राष्ट्रीय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध सभी आंकड़ों में बैगा जनजाति महिलाओं की आय, बचत, ऋण-पहुँच, आजीविका एवं निर्णय-निर्माण क्षमता में सतत और सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होता है, अतः DAY-NRLM के अंतर्गत माइक्रो-क्रेडिट, कौशल विकास प्रशिक्षण तथा SHGs के माध्यम से बैगा जनजाति की महिलाओं को प्रदान किए गए आर्थिक अवसरों का उनके आर्थिक सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

निष्कर्ष:

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में निवासरत बैगा जनजाति की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है।

अध्ययन में प्रयुक्त द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण से यह प्रमाणित होता है कि DAY-NRLM के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से बैगा महिलाओं को संगठित मंच, नियमित बचत, संस्थागत ऋण, कौशल विकास प्रशिक्षण तथा आजीविका के विविध अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की आय में वृद्धि, बचत की प्रवृत्ति का विकास, साहूकारों पर निर्भरता में कमी, तथा स्वरोज़गार एवं सूक्ष्म उद्यमिता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

डिंडोरी जिले के बजाग, करंजिया, समनापुर एवं अमरपुर विकासखंडों तथा चयनित बैगा बहुल ग्राम पंचायतों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि महिलाएँ अब केवल मजदूरी या वनोपज संग्रहण तक सीमित न रहकर कृषि-आजीविका, पशुपालन, लघु व्यवसाय, मूल्य संवर्धन एवं सामुदायिक उत्पादन गतिविधियों से जुड़ रही हैं। इसके साथ-साथ SHGs, ग्राम संगठन (VO) और क्लस्टर स्तरीय संघों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी सुदृढ़ किया है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि DAY-NRLM केवल एक आजीविका कार्यक्रम न होकर, बैगा जनजाति की महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी और समग्र मॉडल सिद्ध हुआ है। प्रस्तुत शोध की परिकल्पना पूर्णतः सत्यापित होती है।

सुझाव

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर DAY-NRLM के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं—

i). **बाज़ार संपर्क को सुदृढ़ किया जाए:** बैगा महिलाओं द्वारा उत्पादित कृषि, वनोपज एवं हस्तशिल्प उत्पादों के लिए स्थायी बाज़ार व्यवस्था, स्थानीय हाट, FPOs एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की आवश्यकता है।

ii). **प्रशिक्षण के बाद निरंतर हैंड-होल्डिंग सुनिश्चित की जाए:** कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उद्यम स्थापना, विपणन और वित्तीय प्रबंधन में निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, ताकि प्रशिक्षण का लाभ दीर्घकालिक बन सके।

iii). **स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को प्राथमिकता दी जाए:** बैगा जनजाति की पारंपरिक आजीविकाओं—वनोपज, जैविक कृषि, औषधीय पौधे एवं पशुपालन—को आधुनिक तकनीक एवं मूल्य संवर्धन से जोड़ा जाए।

iv). **अवसंरचना एवं डिजिटल समावेशन पर ध्यान दिया जाए:**दूरस्थ ग्रामों में परिवहन, भंडारण, बैंकिंग सुविधा और डिजिटल साक्षरता को सुदृढ़ करने से महिलाओं की आर्थिक गतिविधियाँ और सशक्त होंगी।

v). **जनजातीय-संवेदनशील योजना-डिज़ाइन अपनाई जाए:** बैगा जनजाति की सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए योजना को अधिक लचीला और सहभागी बनाया जाए।

References

1. United Nations World Summit for Social Development, Copenhagen Declaration 1995.
2. Behura, B. P., & Patra, K. (2025). Capacity building and economic development of beneficiaries: A study of National Rural Livelihoods Mission in Odisha. *European Economic Letters, 15*(3), 50–59.
3. Pamehgam, D. (2024). *The role of Deen Dayal Upadhyaya National Rural Livelihood Mission in the upliftment of the SHGs in the Sissiborgaon Development Block.* International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), 12(8).
4. Bhavel, S. (2020). राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जनजातीय महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में. Journal of Emerging Technologies and Innovative

Research (JETIR), 7(2), 825–833.
5. Bashir, A., & Khan, A. (2019). *A study on understanding the impact of the NRLM on lives of beneficiaries*. International Journal of Knowledge Management and Practices, 7(1), 71–76.
6. Ministry of Rural Development, Government of India. Deendayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) Progress Reports.
7. Census of India (2011). District Census Handbook: Dindori, Madhya Pradesh.
8. जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश सरकार www.tribal.mp.gov.in.
9. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार. NRLM एवं DAY-NRLM से संबंधित द्वितीयक आंकड़े (https://nrlm.gov.in, https://rural.gov.in)
10. www.dindori.nic.in
11. United Nations World Summit for Social Development, Copenhagen Declaration 1995.